विचार बिन्दु

आत्मा के आनंद रूपी सामंजस्य का बाहरी रूप दया है। –विलियम हैज़लित

राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति

राजस्थान, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक गौरव के लिए जाना जाता है, आज शिक्षा और डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। यह रेगिस्तानी राज्य, जहां कभी जल और संसाधनों की कमी ने विकास को चुनौती दी थी, अब शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के बल पर नई ऊंचाइयां छू रहा है। राजस्थान ने शिक्षा को सुलभ, समावेशी और आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट की शक्ति का उपयोग प्रमुख है।

राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की शुरुआत कुछ साल पहले ही हुई, लेकिन इसकी नींव काफी पहले पड़ चुकी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने देश भर में शिक्षा में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने का रास्ता खोला, और राजस्थान ने इसे उत्साहपूर्वक अपनाया। राज्य सरकार ने शिक्षा को डिजिटल मंचों के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। मिशन बुनियाद इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जिसे 2022 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बढ़ाना, लैंगिक असमानता को कम करना और स्कूल छोड़ने की दर को घटाना था। इस पहल के तहत लगभग 20 लाख विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा प्रदान की गई। यह कार्यक्रम छह जिलों–उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, सीकर, धौलपुर और करौली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुआ, जहां कक्षा 8 से 12 के 24,360 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और उनकी सीखने की क्षमता में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह परिणाम इस बात का सबूत है कि डिजिटल शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रभावी हो सकती है। राज्य में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे पर भी ध्यान दिया गया है।

हाल ही में, 13,976 राजकीय विद्यालयों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) लैब्स स्थापित की गई हैं, जो छात्रों को तकनीकी संसाधनों से जोड़ रही हैं। इसके साथ ही, 13,018 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए गए हैं, जहां इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड और इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाई को रोचक और आधुनिक बनाया जा रहा है। श्री गंगानगर जिले में राजस्थान का पहला डिजिटल स्कूल शुरू किया गया, जो इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये पहल न केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित हैं, बल्कि ग्रामीण स्कूलों को भी डिजिटल संसाधनों से जोड़ा जा रहा है, ताकि शिक्षा की पहुंच हर कोने तक हो। हालांकि, इन उपलब्धियों के बावजूद, राजस्थान में डिजिटल शिक्षा के रास्ते में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी। रेगिस्तानी भूभाग और बिखरी हुई आबादी के कारण कई गांवों में अभी भी विश्वसनीय इंटरनेट सुविधा नहीं है। इसके अलावा, बिजली की अनियमित आपूर्ति डिजिटल उपकरणों के उपयोग को बाधित करती है। ग्रामीण क्षेत्रों के कई स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं, जैसे पर्याप्त कक्षा या प्रशिक्षित शिक्षक, भी कमी है, जिसके कारण डिजिटल शिक्षा का प्रभाव सीमित हो जाता है।

शिक्षकों का तकनीकी प्रशिक्षण भी एक बड़ी चुनौती है। कई शिक्षक, विशेष रूप से पुराने शिक्षक, डिजिटल उपकरणों और ऑनलाइन शिक्षण विधियों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। इसके लिए निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जो समय और संसाधनों की मांग करते हैं। आर्थिक असमानता भी डिजिटल शिक्षा के सामने एक बड़ा रोड़ा है। कई परिवारों के पास स्मार्टफोन, लैपटॉप या इंटरनेट डेटा खरीदने की क्षमता नहीं है, जिसके कारण ऑनलाइन कक्षाओं में उनकी भागीदारी कम रहती है। कोविड–19 महामारी के दौरान यह समस्या और भी स्पष्ट हो गई थी, जब ऑनलाइन शिक्षा एकमात्र विकल्प थी, लेकिन कई छात्र इससे वंचित रह गए। इसके अलावा, डिजिटल साक्षरता की कमी भी एक मुद्दा है। न केवल छात्रों, बल्कि अभिभावकों को भी डिजिटल उपकरणों के उपयोग और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। इन चुनौतियों के बावजूद, राजस्थान ने इनका सामना करने के लिए कई रचनात्मक उपाय किए हैं, जैसे ऑफलाइन डिजिटल सामग्री प्रदान करना और सामुदायिक स्तर पर डिजिटल सेंटर्स स्थापित करना। भविष्य की बात करें तो राजस्थान में डिजिटल शिक्षा की संभावनाएं अपार हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत, राज्य सरकार ने 2025 तक कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग बढ़ाया जा रहा है।

स्टार लिंक जैसी सुविधाओं के लिए सरकार को अभी है खाका तैयार कर लेना चाहिए ताकि दूर संचार के क्षेत्र में राजस्थान धमाकेदार एन्ट्री करें और स्कूली शिक्षा का कायाकल्प हो। चुनौतियां निश्चित रूप से हैं, लेकिन इनका समाधान रचनात्मक और समावेशी दृष्टिकोण से संभव है। भविष्य में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्थानीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री जैसे नवाचार राजस्थान की शिक्षा प्रणाली को और सशक्त बनाएंगे।

भविष्य में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग आधारित शिक्षण मॉड्यूल को अपनाने की योजना है, जो प्रत्येक छात्र की सीखने की गति और जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम को अनुकूलित कर सकते हैं। इसके अलावा, डिजिटल शिक्षा को और समावेशी बनाने के लिए मातृभाषा में शिक्षण सामग्री विकसित की जा रही है, ताकि राजस्थानी और अन्य स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई संभव हो। यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण छात्रों के लिए लाभकारी होगा, जो अक्सर हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ाई को चुनौतीपूर्ण पाते हैं। राजस्थान में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सहयोग भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मिशन बुनियाद जैसे कार्यक्रमों में चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन (सीआईएफएफ) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सहयोग प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, वैश्विक तकनीकी कंपनियां, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, राजस्थान के स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में योगदान दे रही हैं। ये कंपनियां क्लाउड–आधारित शिक्षण मंच और डिजिटल उपकरण प्रदान कर रही हैं, जो शिक्षण को और प्रभावी बना रहे हैं। विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने भी राजस्थान में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह सहयोग न केवल तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराता है, बल्कि वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में भी मदद करता है। उदाहरण के लिए, सिंगापुर और फिनलैंड जैसे देशों के डिजिटल शिक्षा मॉडल से प्रेरणा लेकर राजस्थान अपने पाठ्यक्रम को और नवाचारी बना सकता है। इस डिजिटल क्रांति के पीछे कई नायक भी हैं, जिन्होंने राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नई शिक्षा नीति को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाई है। स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध और संस्कार युक्त शिक्षा पर जोर जैसे कदम उठाए गए हैं, जो शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और मूल्य–आधारित बनाने की दिशा में हैं। इसके अलावा, कई गैर–सरकारी संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, कैवल्य एजुकेशन फाउंडेशन ने मिशन बुनियाद को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने हजारों छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ा। स्थानीय स्तर पर, कई शिक्षक भी अपने सीमित संसाधनों के बावजूद डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर छात्रों को प्रेरित कर रहे हैं। सरकार की भूमिका इस क्रांति को गति देने में सबसे महत्वपूर्ण रही है। राजस्थान सरकार ने न केवल नीतिगत स्तर पर बदलाव किए, बल्कि कार्यान्वयन पर भी विशेष ध्यान दिया।

नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसने विश्वविद्यालयों और स्कूलों में नीति के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को चार श्रेणियों–कक्षा 1 से 5, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12–में संगठित करने की योजना बनाई, ताकि शिक्षा का ढांचा और सुसंगत हो। इसके अलावा, डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए राजस्थान डिजिटल सेवा योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ना है। सरकार ने शिक्षकों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, ताकि वे तकनीक का बेहतर उपयोग कर सकें।हालांकि, सरकार के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। डिजिटल शिक्षा के लिए पर्याप्त बजट आवंटन, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास और शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण जैसे मुद्दों पर और काम करने की जरूरत है। इसके अलावा, डिजिटल शिक्षा के दीर्घकालिक प्रभाव को मापने के लिए एक मजबूत निगरानी और मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता है। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि डिजिटल शिक्षा केवल तकनीकी संसाधनों तक सीमित न रहे, बल्कि यह छात्रों के समग्र विकास में योगदान दे। राजस्थान में शिक्षा और डिजिटल क्रांति का सफर अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसकी दिशा और गति उत्साहजनक है। मिशन बुनियाद, आईसीटी लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम और विदेशी सहयोग जैसे कदम इस दिशा में मजबूत नींव रख रहे हैं। आज अन्य प्रदेशों से सींग लेते हुए राज्य में पहली कक्षा से ही एआई को शिक्षा में जोड़ने की जरूरत है। स्टार लिंक जैसी सुविधाओं के लिए सरकार को अभी से खाका तैयार कर लेना चाहिए ताकि दूर संचार के क्षेत्र में राजस्थान धमाकेदार एन्ट्री करें और स्कूली शिक्षा का कायाकल्प हो। चुनौतियां निश्चित रूप से हैं, लेकिन इनका समाधान रचनात्मक और समावेशी दृष्टिकोण से संभव है। भविष्य में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्थानीय भाषाओं में शिक्षण सामग्री जैसे नवाचार राजस्थान की शिक्षा प्रणाली को और सशक्त बनाएंगे। इस क्रांति के नायक चाहे वे शिक्षक हों, नीति निर्माता हों या सामाजिक कार्यकर्ता राजस्थान को एक ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं, जहां शिक्षा न केवल सुलभ होगी, बल्कि यह हर बच्चे के सपनों को साकार करने का माध्यम भी बनेगी। सरकार की सक्रिय भूमिका और समाज के सहयोग से, राजस्थान निश्चित रूप से डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बन सकता है।

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र मोहन शर्मा
साहित्यकार, शिक्षाविद और चिन्तक

ट्रम्प भाईसाहब, अब बस भी करो

महावीर सिंह

पाकिस्तान के समर्थन–उकसावे से आतंकवादियों द्वारा पहलगांव में गई, 26 निर्दोष पर्यटकों की विभत्स, अमानवीय, अधार्मिक हत्या की घटना के बाद भारत के द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध समुचित दंडनीय कार्यवाही की ही जानी थी। पहलगांव घटना की लगभग विश्व के सम्पूर्ण सभ्य समाज द्वारा भर्त्सना की गई। चीन नें भर्त्सना तो की किन्तु संयम बरतने की सलाह के साथ, तुर्केय व अजरबैजान नें खुलकर भर्त्सना नहीं की। भारत के निकट पड़ोसियों नें भी घटना की मात्र हल्की से आलोचना कर ठंडा सा व्यवहार ही दिखाया। बहुत से भारतीयों की नजर में यह गम्भीर बात है और भारत की शक्तिशाली सरकार को इस ओर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए कि ऐसा क्यों?

पहलगांव घटना 22 अप्रेल 2025 को घटी। भारत द्वारा कार्यवाही की गई 7 मई की रात्रि को। भारत द्वारा पाकिस्तान को दंड देने के स्वरूप पाकिस्तानी पंजाब व पीओके के चिन्हित 22 में से 9 आतंकी ठिकानों, प्रशिक्षण व ठहराव स्थानों, आतंकियों के भारत में घुसने के लॉंचपैडस को ध्वस्त कर दिया गया। यह सेना के शौर्य, प्लानिंग और अचूक निशानों का नतीजा था। भारत का हर नागरिक भारतीय सेना की उत्कृष्टता, बहादुरी, पेशेवराना व विधिसम्मत कार्यशैली को नतमस्तक होकर अभिवादन, सलाम, प्रणाम करता है।

निश्चित: इतनी बड़ी कार्यवाही के लिए सटीक सूचनाओं को एकत्र कर, उनको मध्यनजर रखकर पूरी योजना बनानी पड़ती है, योजना के क्रियान्वयन के लिए तैयारी करनी पड़ती है। विभिन्न महकमों व सेना के विभिन्न अंगों की कार्यवाहियों में समन्वय बैठना पड़ता है। इसके बाद कार्यवाही को अंजाम दिया जाता है। इसमें 15 दिन का समय लगा।

यहां एक सामान्य नागरिक के मन में एक सद्भावी प्रश्न तो उठता है–– ऐसा लगता है कि शायद, भारत के पास आतंकी घटना के घटने के कुछ ही घण्टों में तुरंत कार्यवाही की कोई समुचित, सुविचारित, पूर्वनिर्धारित कार्य योजना नही है।

15 दिन के समय नें पाकिस्तान और उनके द्वारा तैयार आतंकियों को अपने आप को सुरक्षित करने और भारत की जवाबी कार्यवाही से होने वाला नुकसान को कम से कम हो इसके लिए तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया होगा। उनका नुकसान भी कम से कम ही हुआ होगा।आतंकी मरने की प्रतीक्षा थोड़े ही कर रहे होंगे।

कहने वाले कह सकते है कि बाहर बैठ कर सीख देना सबसे आसान काम है। हां काफी हद तक यह ठीक भी है। किन्तु दूसरा पक्ष है कि वर्तमानं में हमारे सेटेलाइट्स पाकिस्तान का, लगभग पूरा भुगोलिक क्षेत्र, हर समय, कवर करते है। उनसे प्राप्त चित्रों के सतत परीक्षण से आतंकी ठिकानों और वहां हो रही गतिविधियों की रियलटाइम ट्रैकिंग सम्भव लगती है। पाकिस्तान लगातार मुंबई की आतंकी घटना, संसद पर हमला, पठानकोट, पुलवामा, उरी व पहलगांव जैसी आतंकी कार्यवाही करता आ रहा है। विगत 10 वर्षों में की गई सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान नही सुधरा। तो फिर पाकिस्तान को सदैव के लिए स्थायी सूचना दे दी जाए कि यदि उसकी धरती से कोई आतंकी घटना भारत पर हुई तो तत्काल अन्य विधि सम्मत सभी प्रकार कार्यवाहियों के साथ साथ, समुचित हवाई हमले किए जांएगे।

इसके लिए आतंकी ठिकानों की दिन–प्रतिदिन आधार पर सही सूचनाएं इक्कठी करते रहना होगा और तत्काल जवाबी कार्यवाही करनी होगी। अगर हमारे सुरक्षा सलाहकारों, विशेषज्ञों का जमावड़ा इसे सम्भव नहीनमंत है तो फिर नियति यही है कि पहले पाकिस्तान कोई बड़ी आतंकी घटना करे और फिर हम 10–15 दिन में उसे सबक सिखा दें और फिर बैठ जाएं।ऐसा कब तक? 7 मई और 10 मई के बीच कई बार पाकिस्तानी सेना नें अतंर्राष्ट्रीय सीमा व लाइन ऑफ कंट्रोल पर, बेजा हरकत करते हुए भारतीय सेना व बेगुनाह नागरिकों पर भारी तोपखाने, ड्रोन्स व मिसाइलस से से हमले किये गए।इस गम्भीर, अवांछनीय हरकत का भारत की सेना नें भी मुनासिब कार्यवाही कर प्रत्युत्तर दिया।इसी कार्यवाही में 10 मई की रात्रि व सुबह पाकिस्तान के 11 बेहद महत्वपूर्ण हवाईअड्डों को पाकिस्तान वायु सेना के लिए अनुपयोगी बना दिये अर्थात एक तरह से पाक वायुसेना को नुमाइसी खिलोने जैसा बना दिया। इनमें रावलपिंडी का हवाईअड्डा (नुरखान एयर बेस) उस स्थान के अत्यंत समीप बताया गया है जहां पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार बताया जाता है।

माना जाता है कि इसके बाद ही पाकिस्तान नें अमरीका सहित कुछ देशों से भारत के हमले रुकवाने का अनुरोध किया। भारतीय पक्ष का कहना है कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन्स नें भारतीय समक्ष से वार्ता की और युद्ध रोकने का अनुरोध किया। उसके बाद युद्ध रोकने की सहमति बनी जिसकी घोषणा भारत के विदेश सचिव नें 10 मई को एक प्रेस कांफ्रेंस में की जिसका सार था कि उस रोज 5 बजे से युद्ध कार्यवाहियां रोक दी गई। वैसे अनपढ़ भारतीय भी जनता है कि भारत की सेना कोई पाकिस्तान की सेना की तरह, थोड़ा ही है जहां सेना युद्ध शुरू और रोकने के लिए बिना सरकार की सहमति/अनुमति के कोई भी निर्णय ले लेती है।। भारत में ऐसे निर्णय जनता की चुनी हुई सरकार के द्वारा ही लिए जाते है अर्थात भारत की सरकार नें 10 मई 2025 को सांयकाल 5 बजे से जल, थल, वायु से कोई युद्धक कार्यवाही न करने सम्बन्धी पाकिस्तानी अनुरोध को मान लिया। सरकार से इसे युद्ध विराम के बजाए संघर्ष विराम कहना ज्यादा पसन्द करती है। लेकिन यहां किसी नें कुछ भ्रम पैदा कर दिया–––––भारत के परम मित्र अमरीका के कुछ उच्चपदस्थ मित्र लोगों ने। वहां के विदेश मंत्री मार्क रुबियो नें कहा कि उन्होंने भारत के प्रधान मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात की और उनसे संयम बरतने की अपील की। भारत नें तो उनसे यह अनुरोध किया नहीं होगा क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां थी उनके रहते भारत को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। इसका अर्थ है कि ऐसा करने के लिए उनसे पाकिस्तान नें अनुरोध किया होगा। यहां तक भी ठीक है। विश्व में जब जहां कही युद्ध की स्थितियां होती है तो कुछ देश लड़ने वाले देशों से शांति की अपीलें करते रहते हैं–कुछ गम्भीरता से तो कुछ यों ही विदेश नीति की एक रूटीन कार्यवाही के रूप में।

पहला गम्भीर प्रश्न तो यह है कि भारत नें यह अनुरोध क्यों माना? भारत के उच्चपदस्थ कई युद्धवीर नेता लोग, उनके अतिकरीबी धर्माचार्यों, कुछ सांस्कृतिक संगठनों के महंतों नें तो यह घोषणा तक कर रखी थी कि अतिशीघ्र निकट भविष्य में तो बस लिया ही मानो। भारत की संसद कई प्रस्तावों के माध्यम से यह दोहरा चूकी कि इ्ध्ख भारत का अभिन्न हिस्सा है। संसद में कई बार छाती ठोक के कहा गया है कि विलय के समय युद्ध विराम की 2–4 दिन की जल्दबाजी की जो गलती तत्समय के हुक्मरानों नें की उसे सुधारने का समय आ गया है।

7 से 10 मई के बीच घटित हुआ और जिस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जैसा, एक तरह से आंखों देखा सा हाल बता रहे थे, उस से तो यही लग रहा था कि पाकिस्तान हथियार डालने ही वाला था। फिर यह अमरीकी अनुरोध मानने का क्या अर्थ? हमारे बयानवीर नेता लोग तो बेचारे थक गए यह बताते बताते कि लड़ाई रोकने के लिए किसी का कोई बाहरी दबाव नहीं था, कोई व्यापार की बात कह कर युद्ध विराम नहीं कराया गया––केवल व केवल पाकिस्तान गिड़गड़ाया तब भारत नें दया दिखा कर बड़े भाई साहब वाला रोल अदा किया।संघर्ष विराम किया है, ओप्रेसन सिंदूर अब भी चालू है अर्थात–––––(जैसा आप चाहो वैसा अर्थ निकालो)। अब यह मीडिया रिपोर्टिंग और संघर्ष विराम की कहानी इतनी सी होती तब तक ठीक था। हमारे जैसे लोगों ने तो बिना मीन मेख के मान लिया था कि जो हमारी सरकार कह रही है वही 100 टक्का सही हैं। किंतु बीच में कूद पड़े, हमारे नेता भाई साहबों के परम मित्र ट्रम्प भाई साहब। ट्रम्प भाई साहब घोषित रूप से भारत के परम मित्र है, जिनके लिए यहां से वहां तक पलक पांवड़े बिछाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। हमारे विदेश सचिव जी नें संघर्ष विराम वाली घोषणा की उसके लगभग साथ सी ही, ट्रम्प भाई जान कुछ कुछ इस प्रकार के अर्थ वाली बातें कह बैठे कि उनके अधिकारियों जे डी वेन्स व मार्क रुबियो नें अथक प्रयास कर, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करा दिया। कोई अत्यंत बड़ी विनाशकारी दुर्घटना हो सकती थी। उस से पहले ही व्यापार का हवाला देकर, होने वाली अत्यंत भयानक घटना रुकवा दी।

अब भारत के अधिकारी लोग कहते रहें कि किसी तीसरे पक्ष का कोई रोल संघर्ष विराम में नहीं किन्तु ठाले बैठे विपक्ष को तो एक मुद्दा पकड़ा ही दिया न ट्रम्प भाई जान नें। अगर एक बार कह के रुक जाते तो भी बात बनी रहती किन्तु ट्रम्प भाई साहब तो रुकने का नाम ही नही ले रहे–––अमरीका में कहा सो कहा विदेशों में भ्रमण कर रहे है वहां भी कुछ कुछ ऐसा ही कह देते हैं। अब तक 6–7 बार घूमा फिरा कर ऐसा स्पस्ट रूप से या सांकेतिक रूप से कह चुके हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लैमी भी पाकिस्तान में आकर कह गए कि ब्रिटेन अमरीका के साथ काम करते हुए भारत पाकिस्तान के मध्य मुद्दे सुलझाने का प्रयास करता रहेगा। इस से भी प्रश्न होता है कि कोई ऐसी बात हुई क्या? अब यहां के कद्दावर नेताओं ने तो पूरा जोर लगा रखा है यह समझने के लिए कि ट्रम्प भाई साहब तो यों ही बोलते रहते है, उन्हें कोई सिरिसली नहीं लेता। यह लोग गिना रहे है कि पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में वर्ष वार कितनी कितनी बार झूठ बोले ट्रम्प भाई साहब।

अब 19 मई 2025 को विदेश सचिव नें यह कहा है कि ट्रम्प स्वमेव बीच में आ रहे हैं तो हम क्या करें। यहां के कुछ मंदबुद्धि लोग और सत्ताधारियों की नजर में कुछ कुछ देशद्रोही टाइप लोग यों ही बात का बतंगड़ बना रहे है। इस वक्त राष्ट्र प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण है कि सरकार की कही बात को 100 टक्का सही मानना ही है। लेकिन फिर भी कुछ सिरफिरे लोग इस बात को ऐसे ही आयी गयी होने ही नहीं दे रहे। चलो छोड़ो जी, यह तो बड़े लोगों की बातें है। एक–दूसरे की टांग, पूँछ, मूछ जो हाथ लगे सो खींचना इन बड़े नेताओं का पसंददीदा खेल बन चुका है लेकिन मेरे गांव का आदमी भी कुछ अटपटे सवाल पूछ लेता है जिनका मेरे जैसे स्वघोषित परम् राष्ट्रवादी के पास भी कोई जवाब नहीं::––(1) बैसरेंन घाटी में जहां 2–3 हजार पर्यटक हर रोज जा रहे थे, सुरक्षा व अन्य सुविधाओं की घोर अनदेखी क्यों थी? (2) 26 पर्यटकों के मौत के जिम्मेदार वो 3–4 आतंकी,आखिर कब तक पकड़े जाएंगे? मार दिए गए या पाकिस्तान में प्रवेश कर गए? (3) ट्रम्प भाई जान बार बार क्यों कह देते है, उन्होंने युद्ध रुकवाया, आण्विक युद्ध का खतरा टलवाया, किसी न्यूट्रल देश में वार्ता का प्रस्ताव दिया वगैरा वैगारा जिसे अखबारों नें कुछ यो छापा है::––

"Donald Trump claims he stopped India Pakistan nuclear war:'Told them gonna do a lot of trade with you"(gonna means I am going to--in general speaking)

Trump once again claims he helped settle India-Pak tensions,--used trade as leverage.

This is the sixth time since Saturday that Trump has claimed that the US brokered the ceasefire between New Delhi and Islamabad.""

सवाल ओर भी थे गांव के लोगों के–––

(4) ठाले बैठे लोगों के पास ओर नही तो यही सवाल है कि पुलवामा के हमलों की सुरक्षा चूक का क्या खुलासा हुआ व चूक पर क्या कार्यवाही हुई (5) यह भी चर्चा कर लेते हैं कि सरकार खुद ही प्रश्न का उत्तर उचित स्तर से दे तो आगे सवाल उठे ही नहीं, क्या कारण है, क्यो ऐसा नही किया जाता? सनसडब्क विशेष सत्र बुलाकर सारी बताने योग्य बातें संसद में बता दे–––क्यों आम आदमी या विपक्ष के सवालों को सेना के शौर्य पर शक का मुलमा चढ़ा कर दफन कर दिए जाते है और सवाल करने वालों को देशद्रोही तक कह जाता है? क्या जो सवाल देश की जनता के मन में है वैसे सवाल अभी विभिन्न देशों में भेजे जा रहे सांसदों से वहां का मीडिया नहीं पूछेगा––उनको तो देश द्रोही कहलाने का डर होगा नही!

इस देश में शायद ही कोई ऐसा हो जिसे देश की सेना के शौर्य, अनुशासन, पेशेवर सक्षमता, वीरता पर भरोसा नही हो किन्तु ऐसा दावा कई नेताओं की देश के प्रति निष्ठा और प्रेम के सम्बंध में निर्विवाद रूप से नहीं किया सकता क्योंकि उनके बोल व कर्म कई बार संशय उत्पन्न करते हैं। ओर जाते जाते, दिल्ली स्थित विकासशील देशों के दूतावास हमारे बड़बोले नेताओं के एक एक बयान, वाक्य, भावभंगिमाओं का विश्लेषण कर अपनी सरकारों को ब्रीफ भेजते हैं और उन देशों के नेता उन्हें ध्यान में रखकर ही हमारे नेताओं से ठक्कर सुहाती बातें करते है। विभिन्न देशों के बीच रिश्तों व राजनीति के विद्वान, विश्लेषक, ज्ञाता मोरगनथा के अनुसार "राष्ट्रों के बीच सम्बन्ध एक शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्र–राज्य मुख्य अभिनेता हैं। उनका उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। राष्ट्र की शक्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। राज्यों को शक्ति और नैतिकता के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए।" शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच के रिश्ते गलबाहियों से तय नहीं होते।

–महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

जन आधार व राशन कार्ड सेवाएं नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान

- **ग्राम पंचायत नान्दला, बुबानिया और धोलादांता बुबानिया के ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को ज्ञापन सौंपा**
- **नगर पालिका में विलय के बाद से काम रुके हुए हैं, सरकार की योजनाओं से वंचित हो रहे ग्रामीण**

नसीराबाद, (निसं)। ग्राम पंचायत नान्दला, बुबानिया और धोलादांता बुबानिया के ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को ज्ञापन सौंपकर जन आधार और राशन कार्ड से जुड़े कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग की है।

ग्रामीणों का कहना है कि नगरपालिका नसीराबाद में पंचायत के विलय के बाद से पिछले दो महीनों से ये कार्य पूर्ण रूप से बंद पड़े हैं।

ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व में श्रीनगर पंचायत समिति के माध्यम से जन आधार, राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने जैसे कार्य सहजता से किए जा रहे थे, लेकिन अब नगर पालिका क्षेत्र में शामिल होने के बाद यह सभी सेवाएं बाधित हो गई हैं। ग्रामीणों ने चिंता जताई है कि खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी रुकी हुई है और यदि समय पर कार्य शुरू नहीं हुए तो बहुत से परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित रह सकते हैं। ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी से मांग की है कि ग्राम पंचायत नान्दला एवं संबंधित गांवों के जन आधार व राशन कार्ड संबंधी कार्यों को शीघ्र पुनः प्रारंभ कराया जाए, ताकि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

नगर पालिका द्वारा सफाई के लिए खुले छोड़े गये नाले आमजन के लिये खतरा बने

पावटा, (निसं)। पावटा प्रागपुरा नगर पालिका क्षेत्र के पावटा कस्बा में नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है।

कस्बे के सुभाष चौक पर नगर पालिका की ओर से नाला अवरुद्ध होने पर सफाई के लिए खोला गया। लोगों ने नगर पालिका अधिकारियों से नाले की सफाई कर उसका पुनर्निर्माण कराने की मांग की, लेकिन नगर पालिका ने बिना चेतावनी बोर्ड के नालों को खुला छोड़ रखा है। ऐसे में अब रास्ते से गुजरने वाले आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नाले की वजह से हादसे की आशंका भी बनी रहती है। नाला अवरुद्ध होने की वजह से नगर पालिका ने जेसीबी से नाले को तोड़ दिया व नाले का सफाई व निर्माण कार्य बंद पड़ा है। व्यापारियों व राहगीरों ने बताया कि नाला ऐसे ही खुला पड़ा है। जिसकी वजह से आम रास्ते से निकलना मुश्किल हो गया है। साथ ही बदबू और मच्छरों से भी लोगों को परेशानी हो रही है।

इस संबंध में क्षेत्रवासियों ने पालिका के अधिकारी को कई बार बताया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि रास्ते में नाला खुदा होने की वजह से मरीजों को लंबा रास्ता तय करके अन्य रास्तों से अपने गंतव्य तक जाना पड़ता है। इतना ही नहीं, रात के समय इस खुले नाले की वजह से दुर्घटना की आशंका भी बनी रहती है। साथ ही क्षेत्र में गंदगी भी पसरी रहती है। क्षेत्रवासियों ने नगर पालिका अधिकारियों से नाले की जल्द सफाई करवाकर ठीक कराने की मांग की है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

बुधवार 22 मई, 2025

ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, दशमी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2082, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र सायं 5:47 तक, विष्कुम्भ योग रात्रि 9:49 तक, वणिजकरण दिन 2:17 तक, चन्द्रमा दिन 12:08 से मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–वृष, चन्द्रमा–कुम्भ, मंगल–कर्क, बुध–मेष, गुरू–मिथुन, शुक्र–मीन, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह राशि में।

आज भद्रा दिन 2:17 से रात्रि 1:31 तक है। आज पंचक है। आज से राष्ट्रीय ज्येष्ठ मास आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 7:21 तक, चर 10:42 से 12:23 तक, लाभ अमृत 12:23 से 3:45 तक, शुभ 5:26 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 5:40, सूर्यास्त 7:07

मेष
आर्थिक मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्यान्ह पूर्व में आर्थिक मामलों में उचित सफलता मिल सकती है। दिन के मध्यान्ह पश्चात अनावश्यक धन खर्च होगा।

वृष
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थ